भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 670
गुरूवार, 28 नवम्बर, 2024/ 7 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

हवाई टिकट की कीमतों में वृद्धि

670. डॉ. के. सुधाकरः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश भर में हवाई टिकट की कीमतों में भारी वृद्धि पर ध्यान दिया है और यदि हां, तो इस संबंध में उठाए गए सुधारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या टिकटों की लागत को कम करने के लिए एविएशन टर्बाइन फ्यूल को जीएसटी के अंतर्गत लाने की योजना बनाई जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अंतर्राष्ट्रीय विमान टिकटों की कीमत कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उपाय किए गए हैं;

(घ) देश भर में उड़ान योजना के अंतर्गत लाए जा रहे नए हवाई मार्गों की सूची क्या है; और

(ङ) क्या यह सच है कि भारत अब विमानों के उत्पादन, मरम्मत और रखरखाव का बाजार बन रहा है और यदि हां, तो बंगलौर को वाणिज्यिक विमानों के उत्पादन, मरम्मत और रखरखाव का केन्द्र बनाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (ग) हवाई किराए भारत सरकार के विनियमन के अध्यधीन नहीं हैं और एयरलाइनें विमान नियम, 1937 के नियम 135 का पालन करते हुए अपनी परिचालन आवश्यकताओं के आधार पर अपने हवाई किराए का निर्धारण कर सकती हैं। हवाई किराए की प्रकृति गतिशील है और, मांग व आपूर्ति के सिद्धांत का पालन करती है। एयरलाइन किराया प्रणाली कई स्तरों (बकेट या आरक्षण बुकिंग डिजिगनेटर) में चलती है, जो वैश्विक स्तर पर अपनाई जा रही पद्धति के अनुरूप है। भारत में हवाई किराए की कीमतों के रुझान में व्यापक स्तर पर मौसमीयता, प्रचलित ईंधन की कीमत, मार्ग पर परिचालन करने वाले विमानों की क्षमता, क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, मौसम, छुट्टियां, त्यौहार, लंबे सप्ताहांत, कार्यक्रम (खेल, मेले, प्रतियोगिताएं), आदि शामिल हैं। इसके अलावा, हवाई अड्डों पर परिचालन बाधाओं से हवाई किराए का मूल्य निर्धारण काफी प्रभावित होता है। मार्गों पर पर्यटकों की अधिक मांग, इलाके, मौसम की स्थिति और प्रतिबंधित परिचालन घंटों द्वारा लगाई गई सीमाओं के अध्यधीन हैं। सीमित क्षमता और बढ़ी हुई मांग के संयोजन से हवाई किराए में उतार-चढ़ाव होता है।

सरकार इस क्षेत्र के विकास को सहयोग प्रदान करने के लिए अनुकूल वातावरण बनाकर सुविधाप्रदाता की भूमिका निभा रही है। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एक टैरिफ मॉनीटरिंग इकाई (टीएमयू) की स्थापना की है, जो मासिक आधार पर एयरलाइनों की

वेबसाइटों का उपयोग करके औचक आधार पर चयनित घरेलू क्षेत्रों पर हवाई किराए की मॉनीटरिंग करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एयरलाइनें उनके द्वारा घोषित सीमा से अधिक हवाई किराया नहीं वसूल रहे हैं।

संविधान के अनुच्छेद 279 क (5) यह निर्धारित करता है कि माल और सेवा कर (जीएसटी) परिषद, पेट्रोलियम क्रूड,हाई स्पीड डीजल,मोटर स्पिरिट (जिसे आमतौर पर पेट्रोल के रूप में जाना जाता है), प्राकृतिक गैस और विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) पर माल और सेवा कर लगाए जाने की तारीख की सिफारिश करेगी। केंद्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी) अधिनियम की धारा 9(2) के अनुसार,जीएसटी में इन उत्पादों को शामिल करने के लिए जीएसटी परिषद की सिफारिश की आवश्यकता होगी। अभी तक,जीएसटी परिषद,जिसमें राज्यों का भी प्रतिनिधित्व है,ने जीएसटी के तहत एटीएफ को शामिल करने के लिए कोई सिफारिश नहीं की है।

(घ) क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) - उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) बाजार आधारित योजना है। इच्छुक एयरलाइनें, विशिष्ट मार्गों पर मांग के अपने आकलन के आधार पर, योजना के तहत बोली प्रक्रिया के समय अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करती हैं।
(ड.) सरकार ने विभिन्न नीति, विनियामक और अन्य प्रोत्साहनों के माध्यम से भारत में विमान रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) सेवाओं की स्थापना को सुलभ बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें शामिल हैं
i. घरेलू रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) उद्योग और इस प्रकार विमानन क्षेत्र को एक अधिक बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने घोषणा की है कि विमानों के कलपुर्जों, घटकों, परीक्षण उपकरणों, औजारों और टूल-किट के आयात पर 5% आईजीएसटी समान दर लागू होगी, चाहे विशिष्ट शर्तों के अध्यधीन उनके नामकरण की संगत प्रणाली (एचएसएन) वर्गीकरण कुछ भी हो।

ii. केंद्रीय बजट 2024-25 में की गई घोषणाओं के तहत, मरम्मत के लिए आयातित वस्तुओं के निर्यात की अवधि छह महीने से बढ़ाकर एक वर्ष कर दी गई है। साथ ही, वारंटी के तहत मरम्मत के लिए वस्तु के पुनः आयात की समय-सीमा तीन से बढ़ाकर पाँच वर्ष कर दी गई है।

iii. दिनांक 1 सितंबर, 2021 को घोषित नए एमआरओ दिशानिर्देश में अन्य बातों के साथ-साथ रॉयल्टी को समाप्त किया गया है और एएआई हवाईअड्डों में एमआरओ के लिए भूमि आवंटन में पारदर्शिता और निश्चयता का प्रदान किया गया है।

iv. दिनांक 1 अप्रैल, 2020 से एमआरओ पर जीएसटी को पूर्ण इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

v. विदेशी मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम)/एमआरओ द्वारा घरेलू एमआरओ को उप-अनुबंधित किए गए संव्यवहार को दिनांक 1 अप्रैल, 2020 से ज़ीरो-रेटेड जीएसटी के साथ 'निर्यात' माना जाता है।

vi. औजारों और टूल किटों पर सीमा शुल्क में छूट।

vii. पुर्जों की सरलीकृत निकासी प्रक्रिया।

vii. एमआरओ के लिए स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति।

उपरोक्त पहलों और सरकार के सक्रिय सहयोग के परिणामस्वरूप, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बेंगलुरु (केआईएबी) को एमआरओ बेस के रूप में विकसित करने की दिशा में उद्योग द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i. अगस्त 2024 में, बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (बीआईएएल) ने एमआरओ बेस विकसित करने के लिए एअर इंडिया समूह के साथ एक समझौता किया है और इस सुविधा को विकसित करने के लिए एअर इंडिया को लगभग 30+ एकड़ भूमि पट्टे पर दी गई है।

ii. इंडिगो के स्वामित्व वाले मौजूदा एमआरओ के अलावा केआईएबी परिसर में एअर इंडिया के लिए एक विमान रखरखाव इंजीनियर प्रशिक्षण सुविधा विकसित की जानी है।

******